दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विज़िट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, सोमवार 06 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 69

महत्वपूर्ण एवं खास

मैदानी इलाकों में हुई बारिश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के पहाड़ों पर पड़ी बर्फबारी

श्रीनगर (आरएनएस)। श्रीनगर में एक सप्ताह से ज्यादा समय के बाद न्यूनतम तापमान बढ़ने के कारण रविवार को मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग (एमईटी) के एक अधिकारी ने कहा, द्रास-कारगिल इलाके और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। अधिकारी ने कहा, श्रीनगर सहित कश्मीर के मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 0.6, पहलगाम में 2.7 और गुलमर्ग में माइनस 1.4 दर्ज किया गया। लद्दाख के द्रास शहर में शून्य से 5.1, लेह में शून्य से 3.6 नीचे, जबकि कारगिल के मापदंडों का इंतजार है। अधिकारी ने कहा, जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 13.6, कटरा में 12.7, बटोटे में 7.5, बनिहाल में 7.8 और भद्रवाह में 7.1 रहा है।

युवाओं को खेल के मैदान पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करें : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आइए हम उत्साह बनाए रखें और अपने युवाओं को खेल के मैदान पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करें। दूरदर्शन न्यूज के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, यह ट्वीट आपको खुशी प्रदान करेगा। आइए हम उत्साह बनाए रखें और अपने युवाओं को खेल के मैदान पर उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करें।

भारतीय सेना की टुकड़ी अभ्यास एक्स एकुवेरिन के 11वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कढधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं को भूमि और समुद्र दोनों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे को समझने, आतंकवाद और विद्रोहियों से निपटने की कार्रवाई आयोजित करने तथा सर्वोत्तम सैन्य कार्यप्रणालियों और अनुभवों को साझा करने के मामले में तालमेल एवं अंतर-संचालन में वृद्धि होगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान कड़े प्रशिक्षण के अलावा, रक्षा सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां भी आयोजित होंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बीच मालदीव के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने के खिलाफ एफआईआर के आदेश

रांची (आरएनएस)। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए माननीय मुख्यमंत्री की फेक आईडी बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉक डाउन की झूठी अफवाह फैलाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश देते हुए आरोपी पर एफआई आर करने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर लॉकडाउन से संबंधित कोई भी ट्वीट नहीं किया है. इसलिए जनता से निवेदन है कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा ना करें.

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, 13 की मौत

जकार्ता। इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सेमरू फूट पड़ा जिससे आसमान में राख का गुब्बार छा गया। इतना ही नहीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकले धुएं और राख के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। ज्वालामुखी के फटने से यहां मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। वहीं इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने बताया कि मरने वाले 13 लोगों में से दो की पहचान कर ली गई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं।

छत्तीसगढ़ को मिला मोस्ट इंप्रुव्हड स्टेट इन इनवायरमेंट अवार्ड

इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडीटर नरोन्हा ने मुख्यमंत्री बघेल को सौंपा पुरस्कार

रायपुर (आरएनएस)। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कान्क्लेव में मोस्ट इंप्रुव्हड स्टेट इन इनवायरमेंट केटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। आज मुख्यमंत्री निवास में इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडीटर राहुल नरोन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पुरस्कार सौंपा। इस अवसर पर जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा भी उपस्थित थे।

इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ दी फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की यह एक बड़ी उपलब्धि है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोहा, कोयला, डोलोमाईट जैसे खनिजों से

परिपूर्ण है। जिसके कारण राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार हुआ है। इन उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहां क्षेत्र के लोगों की आमदनी में भी बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉलिड बेस्ट मेनेजमेंट की चुनौतियां भी मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल इन समस्याओं और चुनौतियों से निपटने में बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित तीन प्रमुख नगर निगमों रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। वायु में सल्फर की मात्रा 37 प्रतिशत तक कम हो गई है। यह 2016 में 26.02 माइक्रोग्राम थी, जो 2020 में घटकर 16.34 माइक्रोग्राम हो गई। इसी प्रकार दैनिक नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड सकेन्द्रण में भी 17 प्रतिशत की कमी आई है। यह 24.11 माइक्रोग्राम से घटकर 19.88 माइक्रोग्राम रह गई है।

इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 28.8 मिलियन आबादी में 6 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों से लगभग एक हजार 650 टन ठोस कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अम्बिकापुर में विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट पृथककरण और रिसायकलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी हानिकारक कचरों के निपटान के लिए अलग से सुविधाएं विकसित की गई है। इसी प्रकार बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिए 4 यूनिट भी प्रस्तावित है। हाल ही में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम राज्य के रूप में सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ लगातार तीन सालों से देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य 44 प्रतिशत वनों से अच्छादित है, इससे ग्रीन हाऊस के प्रभावों को भी कम करने में मदद मिल रही है, वहीं सरकार द्वारा इंडस्ट्रीयल एरिया के 30 प्रतिशत क्षेत्र मी वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में सेना की मदद से भीषण आग पर पाया गया काबू

श्रीनगर (आरएनएस)। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना की मदद से बीती रात भीषण आग पर काबू पाया जा सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम फतेहगढ़, बारामूला के मुख्य बाजार क्षेत्र में 4-5 दिसंबर की रात में लगी भीषण आग ने लकड़ी की घनी दुकानों और आवासों के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। बाजार में आग लगने के बाद आसपास के पेड़ों ने आग पकड़ ली।

शुरूआत में गांव के स्थानीय स्वयंसेवकों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे, जिसके बाद भारतीय सेना से मदद मांगी गई। सेना ने कहा, आग लगने पर प्रतिक्रिया करते हुए, एक त्वरित प्रतिक्रिया दल सहित सेना की दो टीमें अग्निशमन उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं।

सेना के जवानों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, पानी के प्वाइंट से घटना स्थल तक जल्दी से एक ह्यूमन चेन बनाई। आग पर काबू पा लिया गया और आस-पास की दुकानों, घरों और पेड़ों तक नहीं फैलने दिया गया। इस बीच, स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग की दमकल टीम और अन्य सुरक्षा बलों की सहायता से पानी की बौछार और अन्य अग्निशमन उपकरण भी घटना स्थल पर पहुंच गए।

सेना ने कहा, सेना के जवानों ने स्थानीय दमकल विभाग के लिए मार्ग प्रशस्त किया और दमकलकर्मियों के साथ आग को बुझाना जारी रखा। कड़ी मशक्कत के बाद 01.15 बजे आग पर काबू पाया गया।

यह घटना देखने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों ने आग बुझाने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए सेना कर्मियों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ प्रयासों, व्यावसायिकता और साहस की सराहना की, जिससे नुकसान कम हो गया। गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने भी वर्दी में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एकता की भावना के लिए धन्यवाद दिया।

नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी : आज से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीट-पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ अब रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने तेवर कड़े करते हुए कहा कि छह दिसंबर यानी सोमवार से वे देशभर के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 06 दिसंबर को देशभर के अधिकतर बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेगी। फोरडा ने इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर भी मांग की है कि नीट-पीजी की काउंसलिंग जल्द कराई जाए नहीं तो इमरजेंसी सेवाओं का बहिस्कार करेंगे। फोरडा का कहना है कि राष्ट्रीय और राज्य आरडीए के साथ मिलकर यह फैसला लिया गया है। फोरडा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर कुल सौरभ कौशिक ने कहा कि हम सभी पक्षकारों और प्रशासनिक प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि नए डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों ने काउंसलिंग में देरी के खिलाफ प्रदर्शन के तौर पर 27 नवंबर से ओपीडी सेवाएं बंद कर रखी हैं।

राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 127.61 करोड़ से अधिक टीके लगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। 24 घंटों में 1,04,18,707 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 127.61 करोड़ (1,27,61,83,065) के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,32,44,514 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।पिछले 24 घंटों में 6,918 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,40,60,774 हो गई है।

नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.35 प्रतिशत है।

केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 161 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

पिछले 24 घंटे में 8,895 नए मरीज सामने आए हैं।

वर्तमान में 99,155 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय

मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.29 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,26,064 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 64.72 करोड़ (64,72,52,850) जांच की गई हैं।

देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.80 प्रतिशत है जो पिछले 21 दिनों से लगातार 1 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.73 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 62 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 97 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

नगालैंड में सेना के आतंक रोधी अभियान के दौरान 'गलत पहचान' के कारण 13 आम लोगों की मौत

» कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश हुआ जारी

मोन (आरएनएस)। सेना ने नगालैंड के मोन जिले में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान कई आम लोगों की मौत होने के मामले की 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का रविवार को आदेश दिया और इस घटना पर गहरा खेद जताया। नगालैंड की राजधानी कोहिमा में पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों की कथित गोलीबारी में कम से कम 13 आम लोगों की मौत हो गई और वह यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या यह गलत पहचान किए जाने से जुड़ी घटना है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना ओटिंग और तिरु गांवों के बीच उस समय हुई, जब कुछ दिहाड़ी मजदूर शनिवार शाम एक पिकअप वैन के जरिए एक कोयला खदान से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के (एनएससीएन-के) के युंग ओंग धड़े के उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद इलाके में अभियान चला रहे सैन्यकर्मियों ने वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी की।

सेना ने एक बयान में कहा कि लोगों की मौत की इस ''दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के जरिए उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई

की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को घटना की जानकारी दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले मोन जिले में उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया था। सेना ने एक बयान में कहा, ''यह घटना और इसके बाद जो हुआ, वह अत्यंत खेदजनक है। लोगों की मौत की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के जरिए उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसने कहा कि कई सुरक्षाकर्मी अभियान में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक जवान की मौत हो गई है।

इस बीच, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना को ''अत्यंत निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा, ''मोन के ओटिंग में आम लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत

उत्तरकाशी (आरएनएस)। उत्तरकाशी में बीती आधी रात को धरती भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठी। देर रात करीब 2 बजकर 2 मिनट पर आए भूकंप के लगातार दो झटकों से लोगों में दहशत का माहौल रहा। उत्तरकाशी के लोग भूकंप के भय से आधी रात घरों से बाहर निकल पड़े। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई, जिसका केंद्र टिहरी जिले का घनसाली और धनोल्टी रहा। आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तरकाशी जनपद में जब कभी भी भूकंप आता है तो स्थानीय जनमानस भयभीत हो उठता है। लोगों में वर्ष 1991 में आए प्रलयकारी भूकंप की यादें ताजा हो जाती है। भूकंप के लिहाज से सीमांत जनपद उत्तरकाशी जोन 4 व 5 में पड़ता है। ऐसे में भूकंप का आना लोगों के बीच दहशत को और भी बढ़ा देता। बीती आधी रात को 2 बजकर 2 मिनट पर आए 3.8 तीव्रता के भूकंप से उत्तरकाशी की धरती हिल उठी। कुछ देर तक भूकंप के झटकों से स्थानीय जनमानस भय के मारे आधी रात को घरों से बाहर निकल पड़े। जिले के पुरोला, बड़कोट, नौगांव, चिन्यालीसौड़ आदि जगहों पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तेज भूकंप की आशंका के बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा और सारी रात लोग भूकंप के भय से सो नहीं पाए।

उपराष्ट्रपति ने आम आदमी को सेवा प्रदान करने में सुधार हेतु प्रशासनिक सेवाओं में नैतिक पुनरुत्थान की अपील की

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने आज देश में प्रशासनिक सेवाओं के नैतिक पुनरुत्थान का आह्वान किया जिससे आम आदमी को सेवा प्रदान करने में सुधार लाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ लोगों तक पहुंचे।

इस संबंध में, उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता और शासन के सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र के मर्म को नष्ट कर देता है, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के दीर्घ रूप से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने का आह्वान किया।

इसके साथ-साथ, नायडु ने सावधान किया कि वास्तविक सक्रिय कार्रवाई करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को हतोत्साहित या परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन हमें अधिकारियों को व्यापक जनहित में निर्भीक निर्णय लेने से निरूत्साहित नहीं

करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति आज उप-राष्ट्रपति निवास में झारखंड के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के विमोचन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। नायडु ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों में सामान्य रूप से गिरावट आई है और उन्होंने नैतिक भारत के लिए व्यापक आधार वाले सामाजिक आंदोलन का आह्वान किया।

इस संबंध में, नायडु ने ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की उपलब्धियों का सम्मान करने और उनके योगदान की सराहना करने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि यह न केवल युवा अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा, बल्कि इस तरह के प्रचार से दूसरे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने मीडिया को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के ऐसे योगदान को रेखांकित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की सलाह दी।

उद्यमी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करने के अपने अनुभव का स्मरण करते हुए, नायडु ने कहा कि स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों में कई युवा अधिकारी अपने काम में नवोन्मेषण लाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मूल्य आधारित प्रशिक्षण के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पेशागत नैतिकता सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अभिन्न अंग होनी चाहिए। उन्होंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की अनुशंसाओं के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक व्यापक आचार संहिता की अपील की।

एक नैतिक और जन-उत्साही प्रशासनिक अधिकारी के गुणों का वर्णन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक आदर्श अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में मुद्दों की शून्य विचाराधीनता सुनिश्चित करनी चाहिए, कार्यालय में शुचिता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए, लोगों के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने में सक्रिय होना चाहिए और सबसे बढ़कर समाज के सीमांत वर्गों के ध्येय के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।